>

Title: Need to take steps for development of agricultural sector and set up a committee to frame agricultural export-import policy.

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): कृÂिा उत्पादन के आयात-निर्यात की नीति निर्धारण न होने के कारण चीनी, कपास, प्याज, आलू, मिल्क पाउडर, केसीन, चावल, अंगूर, गेहूं आदि कृÂिा उत्पादनों की कीमतों में कम ज्यादा उतर चढ़ाव हो रहा है। परिणामस्वरूप किसानों को अपने लागत मूल्य से भी कम दाम मिलने के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आयात निर्यात शुल्क के बार-बार बदलाव के कारण मंडी में हमेशा के लिए अस्थिरता का वातावरण बना रहता है। उपभोक्ता और मीडिया के दबाव के कारण कृÂिा उत्पादनों के दाम कम रखने के लिए सरकार की विवशता दिखाई देती है। आज उर्वरकों की आसमान को छूती कीततें, डीजल के बढ़ते दाम, कीटनाशक और मजदूरी के बढ़ते दाम और उसके साथ साथ् प्रकृति में होने वाले जलवायु परिवर्तन के चलते किसानों को जी-तोड़ प्रयासों से फसल बचाने के लिए उठाने वाले कÂट, इसके लागत मूल्य में उसका सीधा असर परिणामस्वरूप किसानों को घाटे में खेती के जाने से किसानों के कदम धीरे-धीरे आत्महत्याओं की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं " कॉप-हॉलीडे " लेने की असहायता तो दूसरे तरफ देश के खाद्यान्न सुरक्षा जेसे मुद्दे का एक बड़ी चुनौती के तहत उभरना। सकल घरेलू उत्पादन में कृÂिा क्षेत्र का घटना प्रतिशत्। अतः सरकार को कृÂिा क्षेत्र के विकास और किसानों की बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए तुंत कदम उठाने की नितांत आवश्यकता के साथ् आयात-निर्यात नीति निर्धारण के लिए स्वायत उच्चाधिकार समिति गठित करने की आवश्यकता है।